सत्यमेव जयते

जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार
(विधान मंडल सहित)

बजट
की
प्रमुख विशेषताएं

2024-2025

जुलाई, 2024

वित्त विभाग
बजट प्रभाग

बजट 2024-25 के मुख्य बिंदु

बजट के प्रमुख आंकड़े

प्राप्तियां:

1.	राजस्व प्राप्तियां:	98,719	करोड़ रुपए
2.	पूंजीगत प्राप्तियां:	19,671	करोड़ रुपए
	कुल प्राप्तियां	**1,18,390**	**करोड़ रुपए**

व्यय:

1.	राजस्व व्यय:	81,486	करोड़ रुपए
2.	पूंजीगत व्यय:	36,904	करोड़ रुपए
	कुल व्यय	**1,18,390**	**करोड़ रुपए**

राजकोषीय घाटा:	**7,902 करोड़ रुपए**
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा:	**3.00 %**
जीएसडीपी के लिए पूंजीगत व्यय अंशदान:	**14.01 %**
अपेक्षित जीएसडीपी:	**2,63,399 करोड़ रुपए**
जीएसडीपी में अपेक्षित वृद्धि:	**7.5%**

वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट:

बजट 2024-25 एक विकासोन्मुख बजट है। इसमें जम्मू-कश्मीर के लोगों की महसूस की गई जरूरतों और आकांक्षाओं को शामिल किया गया है। लक्ष्य जम्मू-कश्मीर के नागरिकों की बेहतरी के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास की गति को तेज करना है।

बजट 2024-25 - फोकस क्षेत्र:

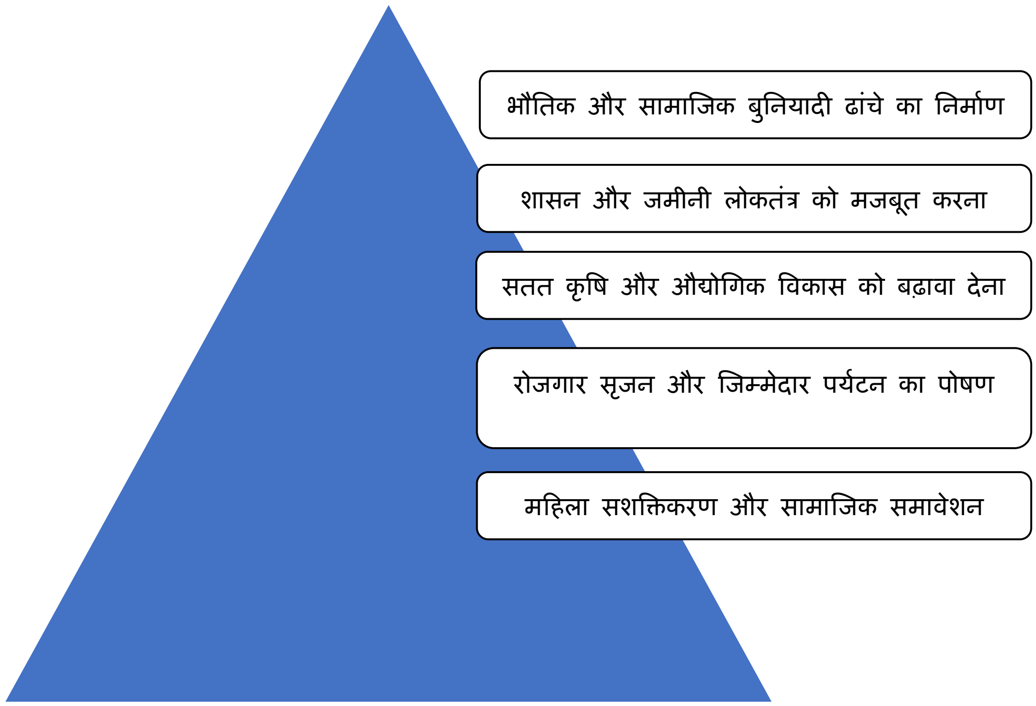

संघ राज्य क्षेत्र के संसाधन

(%प्रतिशत)

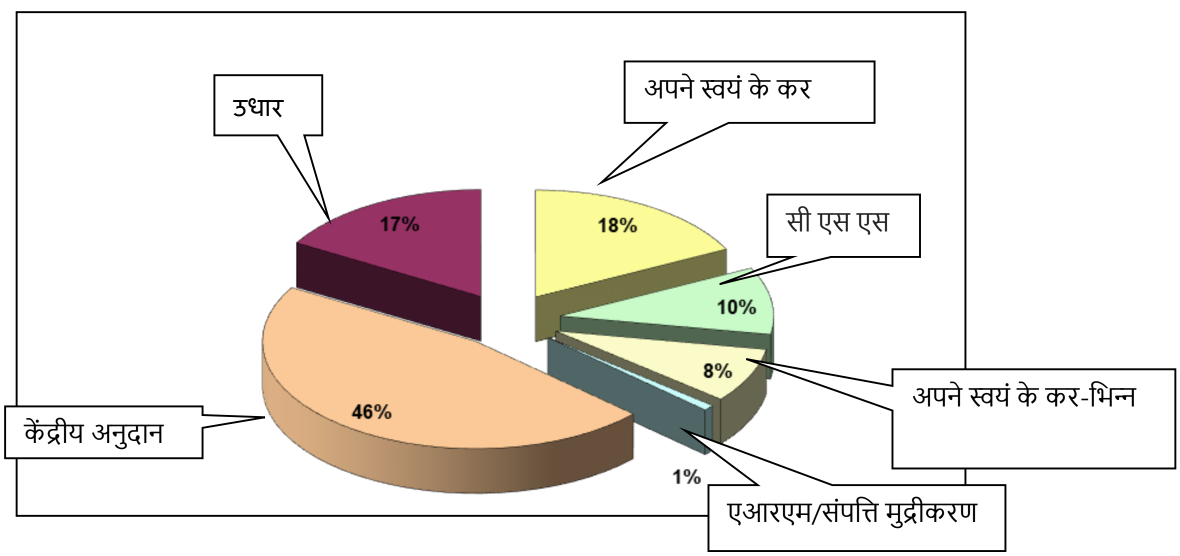

व्यय पैटर्न (%प्रतिशत)

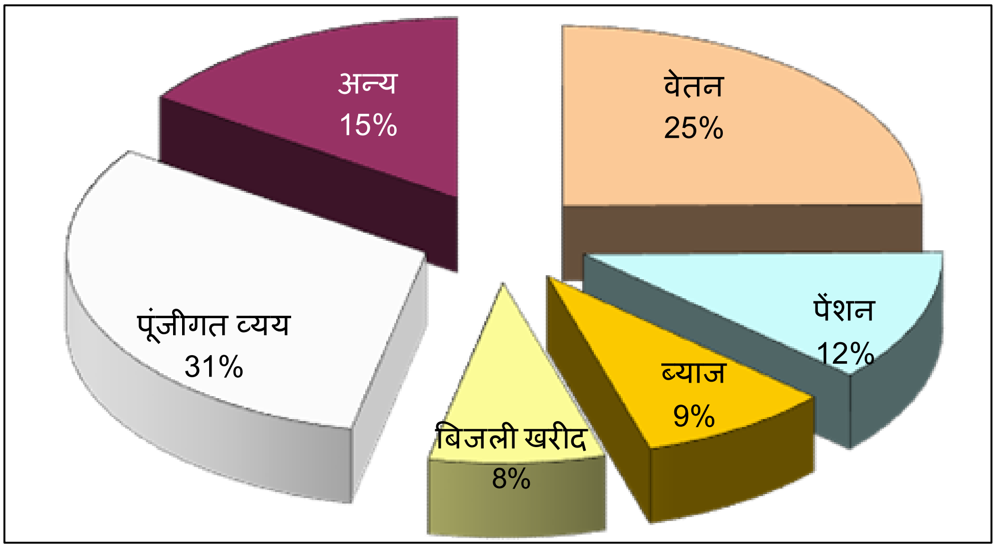

क्षेत्रीय आवंटन

राजस्व व्यय		पूंजीगत व्यय
9881.68 करोड़ रुपए	प्रशासनिक क्षेत्र	1190.50 करोड़ रुपए
24,870.50 करोड़ रुपए रुपए	सामाजिक क्षेत्र	4217.65 करोड़ रुपए
5555.48 करोड़ रुपए	आर्थिक क्षेत्र	6943.20 करोड़ रुपए
15719.40 करोड़ रुपए	बुनियादी ढांचा क्षेत्र	11664.45 करोड़ रुपए

ई-गवर्नेंस की पहलें

1. जम्मू और श्रीनगर में फिजिकल वेरिफिकेशन इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
2. सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) सेल का पुनरुद्धार।
3. पीएम गति शक्ति को पूरी तरह से लागू किया जाएगा.
4. नागरिकों को प्रभावी सेवा वितरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को लागू किया जाएगा।
5. न्यायिक प्रणाली का डिजिटलीकरण।

विभिन्न विभागों/क्षेत्रों की प्रमुख विशेषताएं

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- कृषक समुदाय को घर पर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 2,000 किसान खिदमत घर (केकेजी) की स्थापना। बीज प्रणालियों को सुदृढ़ करके, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देकर, कृषि-व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर और बढ़ी हुई रोजगारों और आय सृजन के माध्यम से आजीविका को सुरक्षित करके समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी) के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना।
- विभागीय बीज गुणन फार्मों को सुदृढ़ करना।
- अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के ऋण के साथ जम्मू और कश्मीर में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार परियोजना (जेकेसीआईपी) को क्रियान्वित किया जाएगा। परियोजना का लक्ष्य कृषि के संचालन की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके ग्रामीण परिवारों की आय में निरंतर वृद्धि में योगदान देना है।
- समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत अनुमोदित सभी 29 परियोजनाओं का कार्यान्वयन।
- 20 कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उत्पादों की पहचान की गई है, जिनमें से 05 उत्पादों (केसर, सुलई शहद, मुश्कबुदगी चावल, भद्रवाह राजमाश और उधमपुर कलारी) को भौगोलिक संकेतक (जीआई) पंजीकरण मिल चुका है और शेष प्रक्रियाधीन हैं।

- कृषि मशीनरी का वितरण जिससे 70,000 किसान लाभान्वित होंगे।
- उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और बागों के कायाकल्प के लिए डिजाइनर पौधों का उत्पादन।
- 25,000 मीट्रिक टन कंट्रोल्ड एटमस्फीयर (सीए) भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी।
- श्रीनगर के चश्मोशाही में गुलदाउदी थीम पार्क का विकास।
- 3,000 डेयरी इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जिससे लगभग 4,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।
- पांच वर्षों की अवधि में दूध उत्पादन में 25 से 45 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि तथा दूध संग्रहण/चिलिंग में 2.0 से 8.5 लाख लीटर प्रतिदिन (एलएलपीडी) की वृद्धि।
- निजी क्षेत्र में 100 सैटेलाइट बछिया पालन इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- 1,800 पशु सखियों को 6,00,000 गायों के लिए राशन बैलेंसिंग तथा 30,000 डेयरी गायों के दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन मिलेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000 बैकयार्ड पोल्ट्री इकाइयां स्थापित की जाएंगी।
- 3,600 हेक्टेयर भूमि के लिए हाइब्रिड चारा बीज किट उपलब्ध कराई जाएंगी।
- चारे की कमी वाले क्षेत्रों में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 100 जलीय चारा इकाइयां तथा 60 साइलिज मेकिंग इकाइयां, साथ ही 6 चारा डिपो स्थापित किए जाएंगे।
- तकनीकी हस्तक्षेप से मछली उत्पादन को 30670 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 35250 मीट्रिक टन किया जाएगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत 400 लाख मानव दिवस सृजित किए जाएंगे।

- हिमायत के तहत लगभग 7000 व्यक्तियों का प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 12,000 अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाए जाएंगे।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत 100% इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ 600 नए पंचायत घर बनाए जाएंगे।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के सदस्यों को 2.60 लाख मानव दिवसों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत 80,000 घरों का निर्माण किया जाएगा।
- 06 गांवों में ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं होंगी ताकि वे कूड़े और प्लास्टिक से मुक्त होकर स्वच्छ बन सकें।
- वर्ष 2024-25 के दौरान एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) के तहत 1800 कार्यों को पूरा करने के साथ 26000 हेक्टेयर क्षेत्र में यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

पर्यटन और संस्कृति

- पर्यटन आकर्षण को बढ़ाने और स्थानीय व्यापार तथा रोजगार के अवसरों का विस्तार करने के उद्देश्य से 12 ऑफ-बीट पर्यटन स्थलों**,** जम्मू और कश्मीर संभागों में प्रत्येक में 6, में अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए नई पहल।
- केरन को सीमावर्ती पर्यटक गांव के रूप में विकसित करना।
- तोसामैदान और सीतारण सर्किट का विकास।
- सांबा में डुग्गर दानी गांव का विकास पारंपरिक व्यवस्था के साथ "मॉक विलेज" के रूप में किया जाएगा।

- पटनीटॉप में 130 मीटर (425 फीट) ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण और स्थापना।
- 75 चिन्हित विरासत स्थलों/सांस्कृतिक स्थलों के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार का कार्य पूरा करना।
- 8 सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना और संचालन।
- श्री प्रताप सिंह (एसपीएस) संग्रहालय श्रीनगर का विकास और आधुनिकीकरण।
- श्रीनगर में अत्याधुनिक सूफियाना स्कूल के संचालन सहित संरचित कार्यक्रमों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में सूफीवाद का प्रचार-प्रसार।
- सभी पुस्तकालयों का डिजिटलीकरण।

वानिकी एवं पर्यावरण

- 190 लाख देशी पेड़ लगाना तथा 100 लाख कम लागत वाले हरित हस्तक्षेप, जिनका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली, मृदा अपरदन को रोकने तथा जैव विविधता को बढ़ाने के लिए है।
- जम्मू एवं कश्मीर के सभी 78 शहरी स्थानीय निकायों में कम से कम एक नगर वन, नगर वाटिका अथवा एक इको पार्क होना चाहिए।
- वनों के बाहर वृक्षों की संख्या बढ़ाने तथा आजीविका में सुधार के लिए किसानों के बीच स्थानीय, औषधीय एवं आर्थिक महत्व की प्रजातियों के 10 लाख पौधे वितरित किए जाने चाहिए।
- इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घराना, होकरसर तथा शालबुघ जैसी आर्द्रभूमियों में अवसंरचना विकसित की जानी चाहिए।
- जम्मू में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) की स्थापना।

- वन से जल, जल से जीवन, जल शेड प्रबंधन दृष्टिकोण के माध्यम से एक अभिनव जल संरक्षण तकनीक का कार्यान्वयन, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा आर्द्रभूमियों सहित पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार करना।
- इकोटूरिज्म के माध्यम से स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए वुलर झील का संरक्षण और पुनरुद्धार।
- पंचायत स्तर की जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की भागीदारी के माध्यम से आजीविका सृजन के अवसरों को बढ़ाना और वन उपज के सतत संग्रह और निपटान के लिए एनआरएलएम के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ उन्हें एकीकृत करना।

सहकारी क्षेत्र

- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।
- जिला/गांव/ब्लॉक स्तर पर मिनी सुपर बाजारों का निर्माण/स्थापना।
- "विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण" योजना के तहत अनाज भंडारण सुविधा की कमी वाले 6 जिलों में 6 अनाज भंडारण इकाइयों का निर्माण।

स्वास्थ्य एवं कल्याण

- वर्ष 2024-25 के दौरान जम्मू और श्रीनगर में दो कैंसर संस्थान पूरी तरह संचालित हो जाएंगे।
- डीएनबी सीटों को बढ़ाकर 400 करना, जिससे विशेषज्ञों की उपलब्धता में सुधार होगा।

- 1.35 करोड़ आबादी के लिए आभा आईडी बनाकर स्वास्थ्य रिकॉर्ड को परिपूर्ण किया जाएगा।
- उच्च रक्तचाप और मधुमेह के लिए 30+ आयु वर्ग के लोगों की शत-प्रतिशत जांच।
- 16 मौजूदा सुविधाओं और 10 नई स्वास्थ्य सुविधाओं में डायलिसिस सेवाओं को और सुदृढ़ किया जाएगा।
- एम्स, अवंतीपोरा को मार्च, 2025 तक कार्यात्मक बनाया जाएगा।
- हंदवाड़ा में नया नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा।
- शेष सभी जिलों को टीबी मुक्त करना।

शिक्षा क्षेत्र

- सभी 13804 स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए 2176 नए बाल विहार स्थापित किए जाएंगे।
- समग्र शिक्षा अभियान के तहत पुस्तकों की खरीद के लिए प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक के स्कूलों को कवर करने के लिए ₹5,000 से ₹20,000 तक का पृथक वार्षिक पुस्तकालय अनुदान।
- छात्रों के पोषण संबंधी स्वास्थ्य में सुधार के लिए मिड-डे मील योजना के तहत प्राथमिक स्तर (I से VIII) के लगभग 8.95 लाख छात्रों को केवल पौष्टिक चावल दिया जाएगा।
- प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के तहत 389 स्कूलों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा।
- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) के तहत 3.50 लाख वयस्कों को साक्षर बनाया जाएगा।

- बीपीएल छात्राओं के लिए बेटी अनमोल योजना के तहत ₹5000 प्रति छात्र की दर से छात्रवृत्ति।
- 18,499 स्कूलों को खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर 16.04 करोड़ रुपये का वित्तीय भार होगा।
- 2,584 स्कूलों को आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम उपलब्ध कराए जाएंगे।
- 43 रोबोटिक लैब और 30 वर्चुअल रियलिटी लैब स्थापित की जानी है।
- 100 स्कूलों में विज्ञान केंद्रों की स्थापना।
- नए 554 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जाएगी।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 05 नव स्थापित कॉलेजों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
- विभिन्न कॉलेजों में दो छात्रावास ब्लॉक, दो विज्ञान ब्लॉक और छह अतिरिक्त व्याख्यान ब्लॉक पूरे किए जाएंगे।
- वर्ष 2024-25 में 08 कॉलेजों तक पहुँच बनाई जाएगी और उन्हें मान्यता दी जाएगी।
- जम्मू और कश्मीर में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) ई-समर्थ के माध्यम से 100% प्रवेश।

सामाजिक/ आदिवासी कल्याण

- सभी दिव्यांग व्यक्तियों को निर्मया स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
- मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों (बालकों/बालिकाओं) के लिए 04 वात्सल्य सदन, जम्मू और कश्मीर, प्रत्येक में दो, संचालित किए जाएंगे।

- 653 आंगनवाड़ी केन्द्रों को बाल विद्यालयों के रूप में उन्नत करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 11 शक्ति सदन और 04 सखी निवासों की स्थापना की जाएगी।
- स्वरोजगार योजना में 1502 इकाइयों की स्थापना के साथ 7,708 महिला लाभार्थियों को लक्षित किया जाएगा।
- 14 पलाश और 13 पारिशा बाल देखभाल संस्थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आधुनिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है।
- जनजातीय आबादी को 250 लघु प्रकार के ट्रैक्टर और लिंक रोड कनैक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- आदिवासी इलाकों में 80 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदला जाएगा।
- प्रवासी जनजातीय आबादी को स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
- ट्रांस-ह्यूमन जनजातीय आबादी के लिए ट्रांजिट आवास स्थापित किए जाएंगे जिसमें 150-200 परिवारों के लिए आवास, सामुदायिक रसोई, चिकित्सा औषधालय, पशु चिकित्सा औषधालय, सामुदायिक शौचालय और पशुधन यार्ड शामिल हैं।
- 500 अनुसूचित जनजाति आबादी वाले 186 गांवों को "प्रधान मंत्री आदि आदर्श योजना (पीएमएएजीवाई)" योजना के तहत कवर किया जाएगा।
- 10 क्लस्टर जनजातीय मॉडल गांवों को 2024-25 में पूरा किया जाएगा।
- 10 दुग्ध गांवों को 2024-25 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कश्मीरी प्रवासियों हेतु राहत और पुनर्वास

- वर्ष 2024-25 के दौरान कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों हेतु ट्रांजिट आवास के रूप में 1500 फ्लैटों के निर्माण को पूरा करना।

- कश्मीरी प्रवासियों के लिए पीएम-पैकेज के तहत 6,000 पदों में से शेष 276 पदों को 2024-25 में भरा जाना है।

खेल और युवा पहलें

- वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत, ब्लॉक, जिला, संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न खेल स्पर्धाओं में 75 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा।
- वर्ष 2024-25 में 20 राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा।
- 200 खेल के मैदान और 100 खेल कोर्ट का निर्माण किया जाएगा।
- मौलाना आजाद स्टेडियम, जम्मू और गिंदुन पार्क राजबाग, श्रीनगर में स्विमिंग पूल का निर्माण पूरा किया जाएगा।

कौशल विकास, युवा सशक्तिकरण और रोजगार

- उद्यमों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इकोसिस्टम बनाने, स्वरोजगार के लिए 5 लाख से अधिक अवसर पैदा करने और ऋण सहायता के माध्यम से निवेश का विस्तार करने के लिए नई पहल।
- 10 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
- बड़े व्यापारिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से 1000 पासआउट छात्रों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किए जाएंगे।

- एनआरएलएम में पंजीकृत 6000 महिला स्व-सहायता समूहों का प्रशिक्षण पूरा किया जाएगा।
- बीज पूंजी निधि योजना, युवा स्टार्ट-अप ऋण योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, महिला उद्यमिता कार्यक्रम जैसी स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से और मिशन युवा योजनाओं के तहत युवाओं को स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- मॉडल करियर केंद्रों (एमसीसी) के माध्यम से नौकरी के इच्छुक लोगों के लिए आउटरीच और परामर्श गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।
- युवा क्लबों के माध्यम से युवाओं का कौशल बढ़ाना।

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले

- प्रधानमंत्री खाद्य अनुपूरक योजना के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति माह 10 किलोग्राम अतिरिक्त चावल प्रदान किया जाएगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी की जाएगी।
- जम्मू और कश्मीर में स्मार्ट पीडीएस की शुरूआत।

विद्‌युत् क्षेत्र

- बिजली की बेहतर उपलब्धता जो पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा देगी तथा इस प्रकार स्थायी रोजगार प्रदान करने एवं समानता को बढ़ावा देने के लिए निर्धनता को दूरकरने, आर्थिक विकास के लक्ष्य को पूरा करेगी।

- सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटरिंग।

- हानि में कमी संबंधी कार्यों का कार्यान्वयन पहले से ही किया जा रहा है। प्रमुख रूप से एलटी-एबी केबलिंग कार्य और बिलिंग दक्षता में सुधार एवं एटी एंड सी घाटे को कम करने के लिए बेयर कंडक्टर को हटाना।
- दोनों अक्षों (बालटाल और पहलगाम) पर पवित्र श्री अमरनाथ जी गुफा तक ग्रिड कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए भूमिगत केबल बिछाने की परियोजना का कार्यान्वयन ।
- उपभोक्ताओं को सुचारू और बाधारहित बिजली आपूर्ति के लिए 105.00 किमी एचटी/एलटी लाइन में सुधार।
- अत्यधिक भारित विद्युत ट्रांसफार्मरों को राहत देने के लिए 35.45 एमवीए सब-स्टेशनों का संवर्धन/निर्माण और बार-बार ब्रेकडाउन तथा लोड शेडिंग से बचने के लिए अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वितरण नेटवर्क के वोल्टेज विनियमन में सुधार लाने और मौजूदा उप-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 38150 केवीए वितरण ट्रांसफार्मर उप-स्टेशनों का निर्माण/संवर्धन।
- अत्यधिक भार वाले 11 केवी फीडरों को अलग-अलग करने के तहत 55 सीकेएम फीडरों को अलग किया जा रहा है ताकि फीडर स्थिरता को बढ़ाया जा सके।
- एलटी नेटवर्क को मजबूत करने और बिजली की चोरी रोकने के लिए एलटी-एबी केबल द्वारा 14,000 सीकेएम जीर्ण-शीर्ण एलटी बेयर कंडक्टर का प्रतिस्थापन। स्मार्ट मीटरों की स्थापना के साथ एलटी-एबी केबल द्वारा बेयर कंडक्टर के प्रतिस्थापन से एटी एंड सी नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
- 11 केवी स्तर पर टी एंड डी हानियों को कम करने के लिए 5,351.53 सीकेएम फीडरों को नए और बेहतर (मोटे) कंडक्टर के साथ नवीनीकृत किया जाएगा।
- 66/11 केवी और 33/11 केवी सब स्टेशनों पर, पीक लोड घंटों में वोल्टेज प्रोफाइल में सुधार के लिए 200 नग कैपेसिटर बैंक स्थापित किए जाएंगे और एमवीए खपत में कमी आएगी।

- 210.60 एमवीए की क्षमता वृद्धि के लिए 31 नग रिसिविंग स्टेशनों (33/11 केवी) की योजना बनाई गई है।
- गुरेज के दूर-दराज और सुदूर क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति प्रदान करना।
- 132 केवी स्तर पर 04 जीएसएस का निर्माण किया जाएगा जो 2024-25 के दौरान 40 एमवीए, 2025-26 के दौरान 100 एमवीए और 2026-27 के दौरान 90 एमवीए की क्षमता बढ़ाएगा।
- 132 केवी स्तर पर 16 जीएसएस को बढ़ाया जाएगा जो 2024-25 के दौरान 556 एमवीए और 2025-26 के दौरान 50 एमवीए की क्षमता बढ़ाएगा।
- 220 केवी स्तर पर 06 जीएसएस को बढ़ाया जाएगा जो 2024-25 के दौरान 90 एमवीए और 2026-27 तक या उससे पहले 720 एमवीए की क्षमता बढ़ाएगा।
- वर्ष 2026-27 तक चरणबद्ध तरीके से 3014.0 मेगावाट स्थापित क्षमता की वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष 10,714.50 मिलियन यूनिट की डिजाइन ऊर्जा की संचयी वृद्धि।

जल शक्ति (जल आपूर्ति और सिंचाई)

- जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत 3,256 जल आपूर्ति योजनाओं में से, 776 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष 2,480 योजनाओं को पूरा करने के लिए एफएचटीसी के साथ शेष 4.26 लाख घरों की कवरेज को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि नल के पानी के कनेक्शन के तहत 100% कवरेज प्राप्त की जा सके।
- सभी 76 उपमंडल स्तर की प्रयोगशालाओं को एनबीएल मान्यता।
- ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के लिए प्रचालन और रखरखाव नीति शुरू करना।

- कौशल विकास मिशन के माध्यम से एनजेएमपी के तहत लगभग 15,000 नल जल मित्रों का प्रशिक्षण।
- लंबित कार्यक्रम के तहत 450 जल आपूर्ति योजनाएं और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ऋण सहायता के तहत 159 जल आपूर्ति योजनाओं को वर्ष 2024-25 में पूरा करने का लक्ष्य है।
- 225 बाढ़ नियंत्रण योजनाएं पूरी की जाएंगी, जो 1,467 हेक्टेयर भूमि को कटाव और बाढ़ के खतरों से बचाएंगी।
- बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) / नदी प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (आरएमबीए) योजना के तहत 16 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरी की जाएंगी।
- शाहपुर कंडी बांध परियोजना चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू होने की संभावना है, जिससे जम्मू-कश्मीर को कठुआ और सांबा में 32186 हेक्टेयर भूमि पर 1150 क्यूसेक सिंचाई जल सुविधाओं का लाभ मिलेगा।
- तवी बैराज का शेष कार्य 2024-25 के दौरान पूरा किया जाना है।
- 2024-25 के दौरान 197 लघु सिंचाई योजनाओं को पूरा किया जाना है, जिसमें 38,723 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता के सृजन की परिकल्पना की गई है।

आवास और शहरी विकास

- 65.33 एमएलडी क्षमता के सीवरेज शोधन वाले 05 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) कार्यान्वयनाधीन हैं।
- अमृत 2.0 के तहत, 78 यूएलबीएस की 153 परियोजनाओं के लिए यूटी वाटर कार्ययोजना पूरी हो चुकी है। इसमें जल आपूर्ति कनेक्शन के लिए 99 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनका लक्ष्य 2.25 लाख नए नल घरेलू कनेक्शन प्रदान करना है। साथ

ही जल निकायों के कायाकल्प के लिए 50 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

- स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 309 परियोजनाओं में से 223 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 86 परियोजनाओं के 2024-25 में पूरा होने की संभावना है।
- पुराने शहर में अवरोधन और डायवर्जन नेटवर्क बिछाने के माध्यम से तवी नदी का प्रदूषण उन्मूलन।
- ट्रांसपोर्ट नगर, नरवाल, जम्मू और परिमपोरा श्रीनगर का पुनरुद्धार ।
- मार्च 2025 तक नगरपालिका ठोस कचरे का 100% स्रोत पृथक्करण।
- जम्मू और श्रीनगर में रिंग रोड के साथ स्मार्ट एकीकृत सैटेलाइट टाउनशिप का विकास।
- पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत 200 ई-बसों की शुरुआत।
- सांबा में बसंतर और श्रीनगर/बडगाम में दूध गंगा नदियों की प्रदूषण उपशमन परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं और उधमपुर में देविका नदी के प्रदूषण उपशमन की परियोजना पूरी की जानी है।
- डल झील, श्रीनगर के साथ पश्चिमी फोरशोर रोड का निर्माण किया जाना है।
- कटरा में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से इंटर मॉडल स्टेशन (आईएमएस) विकसित किया जाएगा।
- सभी 78 शहरों/कस्बों के मास्टर प्लान को अंतिम रूप देना।
- डल-नीगीन झील में हाउसबोटों के सीवरेज नेटवर्क का विकास, जिसमें झील के अंदर बस्तियों का सीवरेज नेटवर्क भी शामिल है।
- गुज्जर नगर और डोगरा हॉल जम्मू में आधुनिक बूचड़खानों का निर्माण।
- चरार-ए-शरीफ, बडगाम में सीवरेज योजना शुरू की जाएगी।

कनेक्टिविटी

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)/शहरों और कस्बों की योजना/केंद्रीय योजना/केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ)/राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ऋण सहायता/गड्ढा मुक्त सड़क योजना के तहत 2024-25 के दौरान 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को ब्लैकटॉप किया जाएगा।
- नाबार्ड के तहत 1023.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत 194 नई परियोजनाओं को वर्ष 2024-25 के दौरान निष्पादन के लिए शामिल किया जाएगा।
- नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये की नई सड़क और पुल परियोजनाएं वर्ष 2024-25 के दौरान आरआईडीएफ किश्त XXX के तहत शुरू की जाएंगी।
- वर्ष 2024-25 के दौरान 60 चालू पुलों के चल रहे कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

औद्योगिक विकास

- निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 46 नई औद्योगिक संपदाओं का तेजी से विकास।

- जम्मू और कश्मीर ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (जे एण्ड के आरईजीपी) के तहत, वर्ष 2024-25 के दौरान 1372 इकाइयों को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
- उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए नई स्टार्ट-अप नीति पेश की जाएगी।
- मौजूदा औद्योगिक संपदाओं में अवसंरचना का उन्नयन।
- निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति में संशोधन किया जाएगा।
- इस वर्ष 324 इकाइयों में उत्पादन शुरू होने की संभावना है जिनमें 18,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

- पीएम-कुसुम घटक "सी" के तहत चरणबद्ध तरीके से 4,000 एसी कृषि पंपों को सौर पंपों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- सरकारी भवनों पर लगभग 04 मेगावाट के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। 22,494 सरकारी भवनों को चरणबद्ध तरीके से 100% सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा।
- पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए डल झील, श्रीनगर में प्रदर्शन के उद्देश्य से 100 किलोवाट तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
- घर के अंदर वायु प्रदूषण और ईंधन के उपयोग को कम करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 उन्नत बायोमास कुक-स्टोव प्रदान किए जाएंगे।
- सौर पार्कों के विकास के लिए भूमि बैंक की पहचान की जाएगी।
- विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएडीपी) के तहत पूर्ण सौरीकरण के लिए पर्यटक और धार्मिक स्थानों को शामिल किया जाएगा।
- श्री अमरनाथ जी यात्रा के सभी मार्गों और शिविरों का सौरीकरण।
- कठुआ में जैव-प्रौद्योगिकी पार्क का प्रचालन।
- स्नातक और पीजी छात्रों के लिए विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति।

- उत्कृष्ट शोधकर्ताओं के बीच युवा वैज्ञानिक पुरस्कार/अध्येतावृत्ति।

परिवहन क्षेत्र

- कोट भलवाल, जम्मू में आईडीटीआर के वर्ष 2024-25 में पूरा और चालू होने की संभावना है।
- सांबा, जम्मू में निरीक्षण और प्रमाणन केन्द्र संस्थान (आईसीसी) के वर्ष 2024-25 में पूरा होने की संभावना है।
- सार्वजनिक परिवहन वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म (वीएलटीपी) का कार्यान्वयन।
- निजी क्षेत्र में मोटर वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) स्थापित किए जाएंगे।
- समय सीमा समाप्त वाहनों (ईएलवी) के लिए वैज्ञानिक तरीके से वाहन के विखंडन और स्क्रैपिंग संबंधी कार्यों के संचालन के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) की नीति की शुरुआत।
- टीआरसी, श्रीनगर में आधुनिक बस टर्मिनल का निर्माण।

प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यकलाप	आवंटन 2024-25 (करोड़ रुपये में)	पहलें
1.	समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)	961	अगले पांच वर्षों की अवधि में 5013 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 29 परियोजनाओं के लिए समग्र कृषि विकास कार्यक्रम।
2.	बागवानी	60	कोल्ड स्टोरेज एवं उच्च घनत्व वृक्षारोपण की स्थापना।
3.	औद्योगिक संपदा	410	निवेश और रोजगार सृजन के लिए नए औद्योगिक संपदा का विकास।
4.	औद्योगिक प्रोत्साहन	48	औद्योगिक नीति और स्टार्ट अप के प्रावधानों के अनुसार प्रोत्साहन।
5.	जीएसटी रिफंड	450	औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रोत्साहन के रूप में जीएसटी रिफंड।
6.	व्यापार संवर्धन	15	जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देना।
7.	रोजगार योजनाएँ	200	युवा स्टार्ट-अप/सीड कैपिटल फंड योजनाएं और युवाओं के स्वरोजगार उद्यमों के लिए मिशन युवा योजनाओं का कार्यान्वयन ।
8.	बैंकों का पूंजीकरण	100	जम्मू-कश्मीर बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों के लिए पूंजी समर्थन।
9.	कनेक्टिविटी	3983	पीएमजीएसवाई, सीआरआईएफ, नाबार्ड ऋण योजना और ब्रिज योजना के तहत सड़कों और पुलों का निर्माण।
10.	नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए इक्विटी	776	रैटल, कावर और किरू जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए इक्विटी समर्थन।
11.	जल जीवन मिशन	1714	सभी घरों के लिए कार्यात्मक नल कनेक्शन।
12.	बाढ़ प्रबंधन	390	झेलम नदी की बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए।
13.	स्वच्छ भारत मिशन (जी)	445	आईएचएचएल, सीएससी और ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ+ स्थिति प्राप्त करना।
14.	सीवरेज प्रबंधन	222	शहरी क्षेत्रों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण ।
15.	नई टाउनशिप	70	आवास हेतु नये टाउनशिप का विकास।
16.	डल विकास	80	डल झील का विकास एवं संरक्षण।
17.	सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ	1430	वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग, लाडली बेटी और विवाह

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यकलाप	आवंटन 2024-25 (करोड़ रुपये में)	पहलें
			सहायता योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता।
18.	जनजातीय कल्याण	70	आदिवासियों के कल्याण के लिए बुनियादी ढांचा जैसे आदिवासी छात्रावास, दूध गांव, खानाबदोश आश्रय और पुस्तकालय।
19.	कश्मीरी प्रवासियों की राहत और पुनर्वास	1068	कश्मीरी प्रवासियों के लिए वेतन, खाद्यान्न, नकद सहायता का प्रावधान और पीएम पैकेज के तहत नियुक्त कश्मीरी प्रवासी कर्मचारियों के लिए पारगमन आवास का निर्माण।
20.	समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए)	1645	एसएसए के विभिन्न घटकों पर व्यय।
21.	पीएम श्री	200	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएम श्री स्कूलों की स्थापना।
22.	गुणवत्ता की शिक्षा	30	बुनियादी ढांचे और कैरियर परामर्श के संबंध में स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार करना।
23.	उच्च शिक्षा	475	कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बुनियादी ढांचे के लिए।
24.	औषधियाँ एवं उपकरण	500	स्वास्थ्य संस्थानों के लिए दवाएँ, मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराना।
25.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम)	1317	एनएचएम के विभिन्न घटकों पर व्यय।
26.	एबी-पीएमजेएवाई (सेहत) योजना	586	जम्मू और कश्मीर के सभी परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज।
27.	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)	1104	ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन गरीब परिवारों को अपना घर बनाने हेतु सहायता ।
28.	पीआरआई और यूएलबी अनुदान	1487	पीआरआई और यूएलबी के विकास कार्य।
29.	डीडीसी/बीडीसी अनुदान	321	बीडीसी एवं डीडीसी के विकास कार्य।
30.	स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षा और आवास	40	डीडीसी/बीडीसी/पीआरआई सदस्यों के लिए आवास और कार्यालयों की सुरक्षा और निर्माण।
31.	पर्यटन क्षेत्र	428	पर्यटन को बढ़ावा देना, नए पर्यटन स्थलों का विकास, नए सर्किट, रोपवे, गोल्फ को बढ़ावा देना और श्री अमरनाथ जी यात्रा का संचालन।
32.	संस्कृति का संरक्षण	120	विरासत संरक्षण, त्योहारों और सिनेमा/थिएटर को बढ़ावा देना।
33.	खेल पहल	140	खेल अवसंरचना का निर्माण ।

क्र.सं.	योजनाएं/कार्यकलाप	आवंटन 2024-25 (करोड़ रुपये में)	पहलें
34.	नवीकरणीय ऊर्जा	150	सौर छतों और सौर पंपों की स्थापना ।
35.	एसआरई और सुरक्षा अवसंरचना	179	सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे का निर्माण, पुलिस आवास कॉलोनी, सीमावर्ती क्षेत्रों में बंकर और पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी की स्थापना।
36.	विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	300	झेलम तवी बाढ़ रिकवरी परियोजना (जेटीएफआरपी) के तहत बुनियादी ढांचे का निर्माण।
37.	फिल्म नीति और प्रचार	90	फिल्म नीति के लिए 10 करोड़ और फिल्म महोत्सव के विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार हेतु 80 करोड़ रुपये।
38.	बिजली खरीद	9400	बिजली की खरीद पर व्यय।
39.	स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ	894	श्रीनगर और जम्मू शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को पूरा करना ।
40.	सीएएमपीए	321	वनरोपण, वन्य जीवन प्रबंधन, जलग्रहण क्षेत्र उपचार, संरक्षित क्षेत्रों का संरक्षण आदि।
41.	एमजी नरेगा	500	ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करता है।
42.	एनआरएलएम	205	आजीविका सृजन के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता।
43.	खेल पहल	145	खेल अवसंरचना का निर्माण ।

PRINTED AT RANBIR GOVERNMENT PRESS, JAMMU